



**INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH –
GRANTHAALAYAH**
A knowledge Repository



जलवायु परिवर्तन और मध्यप्रदेश

अभय जैन

प.म.ब.गुजराती वाणिज्य महाविद्यालय, इंदौर



सारांश

विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की बात लम्बे समय से चली आ रही है, लेकिन विकास चक्र के चलते कहीं न कहीं पर्यावरण की अनदेखी होती आ रही है और ऐसी स्थितियाँ आज हमारे सामने चुनौती एवं संकट के रूप में हैं। अनेक संकल्प, वादे, नीतियाँ और कार्यक्रम आदि के क्रियान्वयन के बावजूद भी पर्यावरण चुनौतियाँ हमारे सामने हैं। मौसम में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव हो रहे हैं, अधिक बरसात या सूखा पड़ना संयोग नहीं बल्कि पर्यावरण परिस्थितियों में आ रहे खतरनाक बदलाव के सूचक और परिणाम हैं।

जलवायु परिवर्तन से निपटना न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिये बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को लाभ पहुँचाने के लिये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव गरीबों और समाज के निचले तबको पर पड़ता है क्योंकि उनके पास साधन सीमित होते हैं।

जलवायु परिवर्तन की वजह से कृषि पर काफी नकारात्मक असर पड़ा है। जिससे पैदावार में कमी के कारण खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो रही है। कृषि सुविधाओं के विस्तार, अनुसंधान व विकास पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि बढ़ते वैश्विक तापमान ने मौसमी घटनाओं की भयावहता, फसलों का नुकसान, पानी की कमी एवं अन्य संकटों में वृद्धि की है। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली विनाशालीला के प्रवाह को रोकने के लिये क्रांतिकारी निर्णय लेने की आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून तो उपलब्ध है किन्तु उनका समुचित पालन और जन चेतना को अधिक सक्रिय करने की आवश्यकता है ताकि विकास और पर्यावरण में संतुलन बना रहे।

प्रस्तावना

पृथ्वी पर मानव जीवन के अवतरण के बाद इसका निरंतर विकास होता रहा, किन्तु मानव को अपने विकास काल में जलवायु संबंधी अनेक समस्याओं एवं परिवर्तनों का सामना करना पड़ा किन्तु इन सब समस्याओं में सर्वमान्य व सबसे चिंताजनक समस्या जलवायु परिवर्तन है। इस समस्या से हमारा वनों का प्रदेश मध्यप्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। मध्यप्रदेश के उत्तरपूर्वी क्षेत्रों – नीमच, मंदसौर, राजगढ़, गुना, आगर, देवास, सिहोर, भोपाल, रायसेन, सागर आदि जिलों में जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। यह क्षेत्र अनाज उत्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पिछले 10 वर्षों में जलवायु परिवर्तन ने यहाँ कृषि आधारित आजीविका और खाद्यान्न उत्पादन पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डाला है। मध्यप्रदेश के उत्तरपूर्वी जिलों में पिछले 9 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में औसतन 6 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। पिछले 4-5 वर्षों में अल्पवर्षा के कारण भूमिगत जल स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। निश्चित रूप से यह कृषि आधारित समाज तथा उसकी आर्थिक स्थिति के लिये गंभीर चिंता का विषय है।

जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अनेकों शोध निष्कर्षों से स्पष्ट है कि आने वाले 30 से 40 वर्षों में पृथ्वी के तापमान में 2 डिग्री व जिस वातावरण में हम रहते हैं उसमें भी 2 से 3 डिग्री तक वृद्धि होगी। हमारे मध्यप्रदेश में विदिशा, बड़वानी और ग्वालियर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ गर्मी के मौसम में तापमान 48 से 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। जलवायु परिवर्तन से हमारा तापमान केवल गर्मी के बढ़ने से ही नहीं है बल्कि जिस मौसम में जो होना चाहिये वह नहीं होने से है। शीत ऋतु में ठण्ड पड़ना चाहिये, हो सकता है कि बहुत ही कम ठण्ड

पड़े। दिसम्बर-जनवरी के समय हम सोचते हैं कि मावठा गिरे पर पिछले वर्षों में मावठा गिरने के चक्र में भारी परिवर्तन देखे गये हैं। इस वर्ष मार्च-अप्रैल में भी बारिश के साथ-साथ ओला वृष्टि हुई। जिससे न केवल स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा साथ ही साथ फसलों को भारी नुकसान पहुँचा। शहर में रहने वाले मध्यमवर्गीय व्यक्ति ने सोचा कि गर्मी से थोड़ी राहत मिली किन्तु यह नहीं सोचा कि यह गर्मी बेतहाशा क्यों बढ़ रही है।

उद्देश्य

1. जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव का अध्ययन।
2. जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन।

हम यह नहीं सोचते कि हमारे घर के उपयोगी सामान फ्रीज, एसी और वाहनों से लगातार प्रदूषण बढ़ने, जंगलों की बेतहाशा कटाई, सड़कों का क्रांक्र्रीट का होना, मिट्टी का कटाव जैसी स्थितियों की इसमें क्या भूमिका है ? इससे भी बढ़कर यह है कि हमारी सरकार ऐसी नीतियाँ बनाती है जिनसे जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिल रहा है। एक तरफ तो जलवायु परिवर्तन में नियंत्रण का एक्शन प्लान बनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ वनों के विनाश और प्राकृतिक सम्पदा को नष्ट कर उद्योगों का विकास किया जा रहा है।

जलवायु परिवर्तन का अर्थ है पर्यावरण के चक्र और उसकी व्यवस्था में अस्वाभाविक परिवर्तन होना। यह परिवर्तन मनुष्य के लिये संकट बन कर उभर रहा है। मौसम के बदलाव से मलेरिया, टायफाइड, कॉलरा और कैसर के मामलों में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। मलेरिया के सबसे ज्यादा प्रकरण मध्यप्रदेश में दर्ज हुए हैं। राज्य की स्वास्थ्य कार्ययोजना एवं समीक्षा दस्तावेज के अनुसार वर्ष 2004 में 1 लाख जनसंख्या पर 405 व्यक्ति अस्थमा से प्रभावित थे जो वर्ष 2015 में बढ़कर लगभग 596 होने का आंकलन है। डायरिया 760 से बढ़कर 880 के लगभग। वर्ष 2004 में कैसर से 8.07 प्रतिशत प्रभावित थे जो बढ़कर 2015 में 9.99 होने का आंकलन है।

मध्यप्रदेश में विकास के नाम पर सड़के बनाने, आधारभूत संरचना विस्तार का कार्य निरंतर जारी है। मध्यप्रदेश में 10 जिलों में सीमेन्ट के उत्पादन के लिये 20,000 हेक्टर जमीन को खदानों में बदल दिया गया, जंगल काटे गये। सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिक विकास की आत्मा में प्रवेश कर चुकी है। क्या सामान्य मनुष्य यह जानता है कि कम्प्यूटर जितनी जहरीली गैसों का उत्सर्जन करता है उसके लिये प्रत्येक कम्प्यूटर के लिये 10 बड़े पेड़ होना चाहिए ताकि वातावरण की क्षतिपूर्ति हो सके। अन्यथा कम्प्यूटर बीमारियों की जड़ बनकर हमें लील जाएगा। साथ ही ग्रीन हाउस गैसों का निरन्तर उत्सर्जन पर्यावरण के चक्र को बदल रहा है।

मध्यप्रदेश में वर्ष 1993-1994 से 2013-14 के बीच 14 से 39 जिले सूखाग्रस्त घोषित किये जाते रहे हैं। सूखा पहले भी पड़ता था किन्तु अब यह जलवायु परिवर्तन का परिणाम है कि मध्यप्रदेश में सूखा एक स्थायी घटना बनता जा रहा है। अब सूखे के बादलों ने मालवांचल की ओर रुख किया है। पिछले 5 सालों में मध्यप्रदेश के 21 जिलों में 20 से 59 प्रतिशत कम बारिश हुई है जिनमें से ज्यादातर मालवा के इलाके में है। सामान्य कृषि का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति यह जानता है कि खेती के लिये बारिश के दिन, समय व मात्रा तीनों महत्वपूर्ण होते हैं। मध्यप्रदेश में ज्यादातर बारिश जून के शुरुआती दिनों में ही हो गई थी। जिससे लोग बुआई नहीं कर सके और फिर तीन-चार बार इतनी तेज बारिश हुई कि बाढ़ के हालात बन गये। जून के मध्य से लेकर जुलाई के मध्य तक बारिश न होने के कारण कृषकों की बुआई नष्ट हो गई और शेष फसल को 21 जुलाई से 5 अगस्त के बीच एक ही दिन में 8 से 15 इंच की बारिश ने नष्ट कर दिया। यह अनियमितता का चक्र सम्पूर्ण कृषि के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र को भी प्रभावित कर रहा है। जिसका एकमात्र कारण जलवायु में हुआ परिवर्तन है।

जलवायु परिवर्तन के कारण

प्रकृति के साथ मनमाने ढंग से छेड़छाड़ के कारण संतुलित जलवायु में असंतुलन उत्पन्न हुआ है और यह एक विकट रूप धारण कर चुका है। वैज्ञानिकों ने भी यह स्वीकार किया है कि औद्योगिकीकरण, शहरीकरण ने प्रकृति को बहुत अधिक क्षति पहुँचायी है। पिछले वर्षों में विषम जलवायु के कारण जान माल की व्यापक

क्षति हुई है। हरित ग्रह प्रभाव एवं ओजोन स्तर का क्षरण पृथ्वी पर हो रहे जलवायु परिवर्तन के संकट को ओर अधिक गंभीर कर रहे हैं।

इस संकट का सबसे बड़ा कारण विकास और औद्योगिकीकरण के लिए कोयले और पेट्रोलियम पदार्थों जैसे फासिल पयूल्स का अंधाधुंध प्रयोग, जनसंख्या वृद्धि, जल का बेहिसाब उपयोग, वनों की अंधाधुंध कटाई, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों व साधनों के उपयोग में वृद्धि से कार्बन उत्सर्जन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इससे भी वायु प्रदूषण बहुत बढ़ा है खेतों में फसल कटने के बाद डंडियों आदि को जलाने के लिये आग लगाई जाती है जिससे धुआ व प्रदूषण बढ़ता है।

निष्कर्ष

जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण जागरूकता

जलवायु में हुए इन परिवर्तनों की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो वह दिन दूर नहीं जब न केवल मध्यप्रदेश और भारत बल्कि सम्पूर्ण विश्व विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपों का शिकार हो जाएगा। इस दिशा में समय रहते ठोस नीतियाँ बनाना अत्यंत आवश्यक है। भारत ही नहीं अमेरिका, चीन कनाडा आदि देशों में वर्तमान में आए प्राकृतिक प्रकोप इसी कड़ी का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक नीतियाँ बनायी जाती हैं किन्तु आर्थिक विकास और दिखावटी उच्च जीवन की लालसा में यह कहीं दफन हो जाती है। जिसका भयानक परिणाम स्वास्थ्य, मानव की कार्यक्षमता और कृषि के साथ-साथ औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है।

पर्यावरण के प्रति जागरूकता भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा है इस दिशा में भारत ही नहीं विश्व के सभी देशों में पर्यावरण जन चेतना के साथ-साथ अनेक कानूनों को बनाया गया है। किन्तु पर्यावरण के प्रति जन चेतना को अधिक सक्रिय करने की आवश्यकता है ताकि विकास एवं पर्यावरण में संतुलन हो।

संदर्भ

1. प्रदूषण पृथ्वी का ग्रहण – प्रेमानंद चंदोला
2. पर्यावरण बोध – डॉ. कल्पना गांगुली, डॉ. संदीप नाकलकर
3. *Environmental Economics - Dr. M.L. Jhingan*
4. पर्यावरण विकास – जून 2014, जनवरी 2014, जनवरी 2015